

संपादकीय

खनन पर हो मनन

पंजाब के प्राकृतिक सुरक्षा कवच पर चोट

सत्ताधीशों की इच्छा शक्ति की कमी और प्रवर्तन एजेंसियों की लापरवाही से खनन माफिया के हौसल बुलंद हैं। कहीं न कहीं नागरिकों की उदासीनता भी इसके मूल में हैं। पंजाब के रोपड़ जिले की शिवालिक पहाड़ियों में हो रही तबाही उस भयावह स्थिति को दर्शाती है, जिसका खमियाजा आने वाली पीढ़ियों को भी भुगतना पड़ेगा। वजह साफ है कि अंधाधुंध खनन से शिवालिक पहाड़ियों के पारिस्थितिकीय तंत्र को भारी क्षति पहुंच रही है। जो हमें यह भी बताता है कि नीति और प्रवर्तन के बीच खाई में पर्यावरणीय अपराध कैसे और किस तेजी से पनपते हैं। प्रशासन की नाक के नीचे खुदाई करने वाली भारी मशीनों का खुलेआम प्रयोग अवैध खनन हेतु किया जा रहा है। इस पारिस्थितिक रूप से नाजुक क्षेत्र की पूरी पहाड़ियों को समतल किया जा रहा है। जो हमारे पर्यावरण के लिये एक गंभीर चुनौती है। यह क्षति शिवालिक पहाड़ियों के मूल पारिस्थितिक कार्यों

“यह शिवालिक पर्वतमाला भू-संरचना की दृष्टि से नयी बनी हुई है और स्वाभाविक रूप से अस्थिर है। निर्विवाद रूप से किसी भी स्थान पर होने वाली अनियंत्रित खुदाई से भूमि का कटाव बहुत तेजी से होता है। जिसके चलते वर्षा ऋतु और उसके बाद भूस्खलन की प्रवृत्ति तेजी से बढ़ती है। वहीं इन क्षेत्रों में गाद जमाव का संकट भी गहरा जाता है। कालांतर इसके चलते जल निकासी के पैटर्न में अप्रत्याशित बदलाव देखने में आता है। यह सर्वविदित है कि एक बार इन पहाड़ियों को अवैध रूप से काटकर समतल कर दिया जाए तो उसके मूल स्वरूप को फिर प्राप्त कर पाना लगभग असंभव है। दूसरे शब्दों में कहें उस क्षेत्र विशेष का प्राकृतिक संरक्षण कवच हमेशा के लिए गूथ हो जाता है। ऐसे में प्राकृतिक सुरक्षा को गूथ करने वाला विकास कालांतर आपदा का कारक बन सकता है।

दरअसल, यह ऐसा प्राकृतिक सुरक्षा तंत्र होता है जो निचले मैदानी इलाकों को बाढ़ और जल संकट से बचाता है। यह विडंबना ही कही जाएगी कि इस बाकत जवाबदेह अधिकारियों द्वारा दलील दी जाती रही है कि इस क्षेत्र में खनन की प्रक्रिया पर्यावरण संबंधी स्वीकृतियों के आधार पर की जाती रही है। साथ ही यह भी सफाई दी जाती है कि ऐसी स्वीकृतियों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाया जाता है। लेकिन हकीकत तब उजागर हो जाती है जब स्थानीय लोग रात के समय होने वाले खनन कार्यों, निर्धारित सीमा से अधिक और बड़े पैमाने पर पहाड़ी इलाकों में कटाई होने के आरोप लगाते हैं। ऐसे में अधिकारियों की तमाम दलीलें खोखली ही साबित होती हैं। दरअसल,सवाल नियम-कानूनों की प्रभावकारिता का नहीं है बल्कि असली दिक़्त प्रवर्तन एजेंसियों की उदासीनता की है। जो वस्तु-स्थिति से अवगत होने के बावजूद इन आपराधिक कृत्यों के प्रति आंखें मूंदे रहती हैं। दरअसल, खनन कार्यों से जुड़े ठेकेदारों को आपराधिक तत्वों व राजनेताओं का संरक्षण भी एक बड़ी चुनौती है। इसमें दो राय नहीं है कि जब अवैध खनन के खिलाफ जमीनी स्तर पर निगरानी के बजाय महज कागजी कार्रवाई का सहारा लिया जाता है तो अवैध खनन को संबल मिलता है। ऐसा भी नहीं है कि यह अवैध खनन केवल पंजाब की शिवालिक पहाड़ियों के आसपास ही हो रहा है।

पूरे भारत में, पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील तमाम क्षेत्रों में अवैध खनन लगातार पर्यावरण से जुड़े कानूनों की सीमाओं का उल्लंघन करता नजर आता है। अकसर खनन के लिये दिए गए परिमिटों में अस्पष्टता और स्थानीय स्तर पर कमजोर निगरानी का फायदा उठाया जाता है। वह भी तब जब सर्वोच्च न्यायालय और राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के फैसलों में बार-बार इस बात पर जोर दिया जाता रहा है कि आर्थिक गतिविधियां पारिस्थितिकीय नुकसान की कीमत पर नहीं चलायी जा सकती। फिर भी, जमीनी स्तर पर, प्रवर्तन एजेंसियां या तो शक्तिहीन दिखाई देती हैं या निर्णायक कार्रवाई करने की इच्छाशक्ति उनमें नजर नहीं आती। वास्तव में अवैध खनन पर सिर्फ जुर्माना लगाने के बजाय प्रतिबंधित क्षेत्रों का सख्त सीमांकन, प्रौद्योगिकी आधारित निगरानी तथा अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने की जरूरत है।

जिम का युवा मालिक वहां पहुंचा। जब उसने शोर मचाने वालों को रोकने की कोशिश की और बाबा स्कूल ड्रेस के उम्रदराज मुसलमान मालिक का पक्ष लिया तो उन उपद्रवियों ने उसे युवक का नाम पूछा। युवक ने बुलंद आवाज़ में अपना नाम बताया मोहम्मद दीपक। उसका नाम दीपक कुमार ही था, पर उपद्रवियों के सामने तनकर खड़ा होते हुए उसने स्वयं को मोहम्मद कहा था। एक मुसलमान पड़ोसी के हितों की रक्षा के लिए किसी हिंदू को सामने आना इस देश के लिए नई बात नहीं है, पर दीपक कुमार का स्वयं को मोहम्मद बताया और वह भी सांप्रदायिकता का ज़हर फैलाने वालों के सामने, साहस की मांग करता है। दीपक कुमार ने यह साहस दिखाया और इस साहस के लिए देश के विवेकशील नागरिक उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। विवेकशील लोगों की कमी नहीं है देश में। पर अन्याय के खिलाफ खड़े होकर न्याय के लिए खरारा मोल लेना भी कोई आसान काम नहीं है। दीपक कुमार ने यह साहस दिखाया है। ऐसे हर दीपक का हौसला बढ़ाने की आवश्यकता है।

जिस दिन अखबार में ‘मोहम्मद दीपक कुमार’ की यह खबर छपी थी, उसी दिन एक खबर देश की पूर्वी सीमा से भी आयी थी। असम की बात है यह। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा का एक बयान छपा था अखबारों में। वह कह रहे थे कि मुसलमान रिक्शा चालक को हिंदुओं से कम मेहनताना देना चाहिए। कोई भी यदि इस तरह के भेदभाव वाली बात कहे तो उसे गुलत ही कहा जायेगा। पर यदि कोई मुख्यमंत्री ऐसी बात करता है तो उसकी सोच पर गुस्सा ही

सौरभ गर्ग

महंगाई देश के सबसे अहम आर्थिक संकेतकों में से एक है, जिसे आम लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सीधे महसूस करते हैं, जैसे घर का राशन, किराया और पेट्रोल-डीज़ल के खर्च में बढ़ोतरी से।



उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) इसी महंगाई को मापता है। यह उन चीज़ों और सेवाओं के दाम देखाता है, जिनका इस्तेमाल आम परिवार रोज़ करता है। सरल शब्दों में, सीपीआई आम आदमी की ज़िंदगी का आईना है। यह बताता है कि थाली में खाने का खर्च कितना बढ़ा, घर का किराया कितना हुआ, और काम पर जाने के लिए ईंधन कितना महंगा हुआ।

सीपीआई भले ही एक आंकड़ा लगता हो, लेकिन यह सरकार को यह समझने में मदद करता है कि लोगों पर महंगाई का असली असर क्या है। इसी आधार पर वेतन, पेंशन और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े फैसले किए जाते हैं, ताकि ज़रूरी चीज़ें आम लोगों की पहुंच में बनी रहें।

भारतीय रिज़र्व बैंक भी ब्याज दर और महंगाई को नियंत्रित करने जैसे फैसलों के लिए सीपीआई आधारित महंगाई को ही सबसे मुख्य पैमाना मानता है। इसलिए जब सीपीआई ज़मीन की हकीकत सही तरीके से दिखाता है, तब सरकार और आरबीआई की नीतियां भी लोगों की असली परेशानियों के अनुसार बेहतर बन पाती हैं। महंगाई सिर्फ दाम बढ़ने का नाम नहीं है, बल्कि यह भी है कि दामों में बदलाव से घर के बजट पर कितना असर पड़ता है। इसलिए जितना ज़रूरी दामों को मापना है, उतना ही ज़रूरी यह भी है कि महंगाई का सूचकांक लोगों की आज की खर्च करने की आदतों को सही तरीके से दिखाए। इसी संदर्भ में भारत में सीपीआई के आधार वर्ष को 2012 से बदलकर 2024 किया जा रहा है।

पिछली बार आधार बदले जाने के बाद देश की अर्थव्यवस्था में बहुत बदलाव आया है। शहरों की आबादी बढ़ी है, सेवाओं का क्षेत्र बढ़ा है, डिजिटल प्लेटफॉर्म के कारण खरीदारी का तरीका बदला है और घरों का खर्च अब कई नई चीज़ों पर होने लगा है।

इसीलिए नया सीपीआई 2024 तैयार करने में 2023-24 के घरेलू उपभोग व्वय सर्वेक्षण के आंकड़ों का इस्तेमाल किया गया है।

समय के साथ लोगों की ज़रूरतें और खर्च बदलते हैं, इसलिए सीपीआई में अलग-अलग वस्तुओं और

नसीम अहमद खान

छत्तीसगढ़ आज ग्रामीण विकास के उस मुकाम पर खड़ा है, जहाँ नीतियाँ केवल कागज़ों तक सीमित नहीं रहीं, बल्कि ज़मीन पर ठोस बदलाव का माध्यम बन चुकी हैं। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने सुशासन को केवल एक सिद्धांत नहीं, बल्कि कार्यशैली के रूप में अपनाया है। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), महात्मा गांधी नरेगा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जैसी योजनाओं के प्रभावी और पारदर्शी क्रियान्वयन ने छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर ग्रामीण विकास का एक उभरता मॉडल बना दिया है।

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत बीते दो वर्षों में छत्तीसगढ़ में 8 लाख से अधिक पक्के आवासों का निर्माण पूर्ण होना, देश में सर्वाधिक है। यह उपलब्धि केवल आंकड़ों की कहानी नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय और गरिमापूर्ण जीवन की दिशा में एक बड़ा कदम है। मुख्यमंत्री साय का मानना ​​है कि आवास केवल छत नहीं, बल्कि सुरक्षा, स्थिरता और आत्मसम्मान का आधार है। यही कारण है कि राज्य सरकार ने आवास योजना को आजीविका से जोड़ा है। आवास हितग्राहियों को सेंटरिंग प्लेट एवं



अन्य निर्माण की आपूर्ति कर 8 हजार से अधिक महिलाएँ 'लखपति दीदी' बन सकीं।

छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी चुनौती रहे नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सरकार ने सुरक्षा के साथ-साथ विकास और विश्वास को समान महत्व दिया है। कौशल प्रशिक्षण और पुनर्वास योजनाओं के माध्यम से युवाओं को मुख्यधारा से जोड़ा जा रहा है। आर-सेटी एवं प्रोजेक्ट उन्नति के जरिए आत्मसमर्पित नक्सलियों सहित 5 हजार से

अधिक हितग्राहियों को राजमिस्त्री का प्रशिक्षण दिया गया है। वहीं, 3416 आत्मसमर्पित नक्सलियों और नक्सल पीड़ित परिवारों को आवास की स्वीकृति दी गई है। पीएम-जनमन आवास योजना के अंतर्गत विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए 33 हजार से अधिक आवासों की स्वीकृति इस दिशा में एक ऐतिहासिक पहल मानी जा रही है।

साय सरकार ने योजनाओं की निगरानी में आम नागरिक को सहभागी बनाकर

विचार

सीपीआई के आधार वर्ष में बदलाव क्या बदला है और यह क्यों जरूरी है



सेवाओं को दी जाने वाली अहमियत भी बदली गई है। जिन चीज़ों पर अब परिवार ज्यादा खर्च करते हैं, उन्हें सीपीआई में ज्यादा महत्व दिया गया है, और जिन पर खर्च कम हो गया है, उन्हें कम महत्व दिया गया है। इससे सीपीआई वही महंगाई दिखाता है, जो सच में आम परिवार के बजट को प्रभावित करती है। साथ ही, उपभोग की टोकरी (कंजम्पशन बास्केट) को भी बदला गया है, ताकि सेवाओं पर बढ़ते खर्च जैसे नए रूझान दिखाई दे सकें, जो बढ़ती आय और बदलती जीवनशैली की वजह से बढ़ रहे हैं। सीपीआई को मापने का तरीका अपडेट करना भी उतना ही ज़रूरी है, जितना यह तय करना कि उसमें क्या-क्या शामिल किया जाए।

नया संशोधित सीपीआई अब अंतरराष्ट्रीय मानकों के ज्यादा करीब है, लेकिन इसमें भारत से जुड़ी खास बातें भी बनी हुई हैं। इससे भारत की महंगाई की तुलना दूसरे देशों से करना आसान हो जाता है।

आम परिवार के लिए इसका मतलब यह है कि सरकार और नीति बनाने वाले लोग यह बेहतर समझ पाते हैं कि भारत में दामों में होने वाला बदलाव दुनिया के हालात से कैसे जुड़ा है, और साथ ही यह भी ध्यान रहता है कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर क्या असर पड़ रहा है।

सीपीआई के लिए आंकड़े जुटाने का तरीका भी अब लोगों की बदलती खरीदारी और खर्च की आदतों के अनुसार बेहतर बनाया गया है। जहां पहले की तरह

बाजारों से दाम इकट्ठा किए जाते रहेंगे, खासकर खाने-पीने और ज़रूरी चीज़ों के, वहीं 2024 के नए ढांचे में अब कुछ सेवाओं के ऑनलाइन दाम भी शामिल किए जा रहे हैं। जैसे मोबाइल और इंटरनेट सेवाएं, हवाई टिकट और कुछ अन्य सेवाओं के दाम अब ऑनलाइन स्रोतों से भी लिए जाएंगे।

नई सीपीआई श्रृंखला में अब कंप्यूटर की मदद से दाम इकट्ठा किए जा रहे हैं। इससे हाथ से होने वाली गलतियाँ कम हुई हैं और तुरंत जाँच भी हो जाती है। इससे दामों से जुड़े आंकड़ों की गुणवत्ता और समय पर उपलब्धता दोनों बेहतर हुई हैं। सीपीआई के आंकड़े सही और समय पर मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी के आधार पर ऐसे फैसले होते हैं, जो सीधे आम आदमी की ज़िंदगी को प्रभावित करते हैं, जैसे कर्ज कितना महंगा होगा, बचत पर कितना ब्याज मिलेगा, और बढ़ती महंगाई से घर का बजट कैसे प्रभावित होगा।

नए आधार वर्ष की सीपीआई में अब कई मामलों में सरकारी स्रोतों से मिलने वाले आधिकारिक आंकड़ों का ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे रेल किराया, डाक शुल्क, ईंधन के दाम और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत बिकने वाली चीज़ें। इससे इन दामों को पहले से ज्यादा सही तरीके से दर्ज किया जा रहा है और बाजार सर्वे में होने वाली गलती या पक्षपात की संभावना भी कम हो जाती है।

अब सर्वे के आंकड़े, सरकारी रिकॉर्ड और

डिजिटल माध्यमों से मिलने वाले दाम, तीनों को मिलाकर सीपीआई तैयार की जा रही है। यह पुरानी व्यवस्था की तुलना में बड़ा सुधार है और इससे दामों में होने वाले बदलाव की ज्यादा भरोसेमंद तस्वीर मिलती है। इतने बड़े स्तर पर सीपीआई के आधार वर्ष में बदलाव करना एक बहुत बड़ा संस्थागत प्रयास होता है। इसमें देश भर के फील्ड दफ्तरों, सांख्यिकी विभागों और राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञ संस्थाओं के बीच तालमेल ज़रूरी होता है। इस पूरी प्रक्रिया में मैथडोलॉजी की गहराई से जाँच की जाती है, अलग-अलग विकल्पों को परखा जाता है और अर्थशास्त्रियों व विषय-विशेषज्ञों से सलाह ली जाती है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने विशेषज्ञ समूहों, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं और अन्य संबंधित पक्षों से बातचीत की है, ताकि किए गए बदलाव साफ समझने में आसान और वैज्ञानिक रूप से सही हों।

टोकरी, नेटेज और आंकड़ों के स्रोत बदलने के बाद भी सीपीआई का मूल उद्देश्य वही रहता है-यानी एक परिवार की नजर से दामों में होने वाले बदलाव को दिखाना। यह निरंतरता इसलिए ज़रूरी है, ताकि हम समय के साथ महंगाई की तुलना कर सकें।

सीधे शब्दों में, सीपीआई को बेहतर बनाया जा रहा है, लेकिन उसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जोड़कर ही रखा गया है, ताकि वह नीति बनाने वालों के लिए एक भरोसेमंद मार्गदर्शक बना रहे।सीपीआई हमें यह याद दिलाता है कि हर आंकड़े के पीछे करोड़ों लोगों की असली ज़िंदगी छिपी होती है। आखिरकार, आंकड़े लोगों के लिए ही होते हैं। यह चुपचाप यह दिखाता है कि दामों में बदलाव हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को कैसे प्रभावित करता है और सरकार की नीतियों को दिशा देता है।

आधार वर्ष में चल रहे संशोधन के जरिये सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने यह सुनिश्चित किया है कि सीपीआई सही, समय के अनुसार अपडेट और लंबे समय तक एक-जैसे तरीके से मापा गया रहे। ताकि सीपीआई सिर्फ एक संख्या न होकर, पूरे देश के लोगों की असली ज़िंदगी की सच्चाई दिखाने वाला आईना बना रहे।

(लेखक सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव हैं, यह उनके निजी विचार हैं)

ग्राउंड से ग्ोध तक : छत्तीसगढ़ में साय सरकार का सुशासन मॉडल

पारदर्शिता को नई परिभाषा दी है। टोल-फ्री हेल्पलाइन, पंचायत स्तर पर क्यूआर कोड और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से कोई भी व्यक्ति विकास कार्यों की जानकारी सीधे प्राप्त कर सकता है। प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को मनरेगा, उज्ज्वला, स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन मिशन और पीएम सूर्यग्र जैसी योजनाओं से अभिसरण के माध्यम से जोड़ा गया है, जिससे समग्र लाभ सुनिश्चित हो रहा है।

‘मोर गांव मोर पानी’ महाभियान छत्तीसगढ़ की जल संरक्षण नीति का प्रतीक बनकर उभरा है। नरेगा के तहत दो वर्षों में 20 करोड़ से अधिक मानव दिवसों का सृजन हुआ है। जल संरक्षण के लिए 35 हजार से अधिक कार्य और 10 हजार से अधिक आजीविका डबरियों की स्वीकृति ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती दी है। युक्तधारा पोर्टल के माध्यम से जीआईएस आधारित योजना निर्माण में छत्तीसगढ़ ने देश के अग्रणी राज्यों में स्थान बनाया है।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 2.82 लाख से अधिक स्व-सहायता समूहों से लगभग 30 लाख महिलाएँ जुड़ी हैं। ‘लखपति दीदी’ अभियान के माध्यम से अब तक 4.94 लाख महिलाएँ आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन चुकी हैं। महिलाओं की आवाज़ को मंच देने के लिए ‘दीदी के

गोट’ रेडियो कार्यक्रम और उनके उत्पादों के विपणन हेतु ‘छत्तीसकला’ ब्रांड राज्य सरकार के नवाचारों के प्रमाण हैं।

प्रधानमंत्री जनमन योजना के अंतर्गत 2902 किलोमीटर सड़कों की स्वीकृति और 1064 किलोमीटर सड़कों का निर्माण पूर्ण होना, दूरस्थ और जनजातीय अंचलों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने की दिशा में बड़ा कदम है। प्रधानमंत्री जनमन योजना के अंतर्गत स्वीकृत सड़कों के निर्माण में छत्तीसगढ़ देश में अग्रणी राज्य है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के विभिन्न चरणों में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में दशकों से अधूरी पड़ी 43 सड़कों को पूरा कर सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि विकास अब किसी क्षेत्र या वर्ग तक सीमित नहीं रहेगा।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का कहना है कि शासन का वास्तविक उद्देश्य आम नागरिक के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना है। आवास, रोजगार, महिला सशक्तिकरण, जल संरक्षण और अधोसंरचना के समन्वित प्रयासों से छत्तीसगढ़ आज समावेशी और आत्मनिर्भर विकास की दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। पारदर्शी, नवाचारी और जनोन्मुखी कार्यप्रणाली के कारण छत्तीसगढ़ अब केवल एक राज्य नहीं, बल्कि ग्रामीण विकास का राष्ट्रीय मॉडल बन रहा है।

उप संचालक जनसंपर्क

तंग नजरिये से छोटा न हो भारतीयता का आंगन

विश्वनाथ सचदेव

देश के हर विवेकशील नागरिक के मन में यह सवाल उठना चाहिए। भारतीयता के आंगन में धर्म की दीवारें खड़ी करने वालों को यह बात क्यों समझ नहीं आ रही कि ऐसी हर दीवार आंगन को छोटा ही करती है। आज अपने आंगन को बांटना नहीं है, पूरे आंगन में धूप की ऊष्मा और रोशनी पहुंचाना हमारी आवश्यकता है। अखबार में उस दिन दो खबरें एक साथ दिखीं। पहली खबर उत्तराखंड के कोटद्वार की है। वहां एक दुकान है, स्कूली ड्रेस बिकती हैं वहां। नाम है ‘बाबा स्कूल ड्रेस और मैचिंग सेंटर’। पिछले 30 साल से चल रही इस दुकान के 75 वर्षीय मुस्लिम मालिक को कुछ लोग धमका रहे हैं कि वह दुकान का नाम बदले बाबा शब्द को हटा दें। भले ही आप अपने पिता को बाबा कहते हैं पर इस दुकान का नाम बदलवाने की मांग करने वालों का कहना है कि कोटद्वार में बाबा सिद्धबली का मंदिर है। उन्हें लगता है कि इस ‘बाबा’ नाम पर हिंदुओं का एकाधिकार है और किसी मुसलमान को अपनी दुकान का नाम हिंदुओं के देवता के नाम पर रखने का अधिकार नहीं है। अपने आप को हिंदू धर्म का रक्षक मानने वालों की उस भीड़ ने कुछ दिन पहले भी इस नाम को बदलने की मांग की थी, और अब फिर इस बात का जवाब मांग रहे थे कि ‘अब तक नाम बदला क्यों नहीं गया। यह जानना जरूरी है कि उस भीड़ के लोग अग्रह नहीं कर रहे थे, धमका रहे थे। उनकी धमकियों का शोर सुनकर पास के

जिम का युवा मालिक वहां पहुंचा। जब उसने शोर मचाने वालों को रोकने की कोशिश की और बाबा स्कूल ड्रेस के उम्रदराज मुसलमान मालिक का पक्ष लिया तो उन उपद्रवियों ने उसे युवक का नाम पूछा। युवक ने बुलंद आवाज़ में अपना नाम बताया मोहम्मद दीपक। उसका नाम दीपक कुमार ही था, पर उपद्रवियों के सामने तनकर खड़ा होते हुए उसने स्वयं को मोहम्मद कहा था। एक मुसलमान पड़ोसी के हितों की रक्षा के लिए किसी हिंदू को सामने आना इस देश के लिए नई बात नहीं है, पर दीपक कुमार का स्वयं को मोहम्मद बताया और वह भी सांप्रदायिकता का ज़हर फैलाने वालों के सामने, साहस की मांग करता है। दीपक कुमार ने यह साहस दिखाया और इस साहस के लिए देश के विवेकशील नागरिक उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। विवेकशील लोगों की कमी नहीं है देश में। पर अन्याय के खिलाफ खड़े होकर न्याय के लिए खरारा मोल लेना भी कोई आसान काम नहीं है। दीपक कुमार ने यह साहस दिखाया है। ऐसे हर दीपक का हौसला बढ़ाने की आवश्यकता है।

जिस दिन अखबार में ‘मोहम्मद दीपक कुमार’ की यह खबर छपी थी, उसी दिन एक खबर देश की पूर्वी सीमा से भी आयी थी। असम की बात है यह। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा का एक बयान छपा था अखबारों में। वह कह रहे थे कि मुसलमान रिक्शा चालक को हिंदुओं से कम मेहनताना देना चाहिए। कोई भी यदि इस तरह के भेदभाव वाली बात कहे तो उसे गुलत ही कहा जायेगा। पर यदि कोई मुख्यमंत्री ऐसी बात करता है तो उसकी सोच पर गुस्सा ही



नहीं आता, तरस भी आता है। मुख्यमंत्री जैसे जिम्मेदार पद पर बैठा कोई व्यक्ति यदि इस तरह की घटिया सोच का प्रदर्शन करता है तो बात और भी गंभीर हो जाती है। यह दुर्भाग्य ही है कि आज़ादी अर्जित करने के इतने साल बाद इस तरह की सोच के उदाहरण सामने आ रहे हैं। जब हमारे पूर्वजों ने देश के संविधान में पंथ-निरपेक्ष भारत की व्यवस्था की थी तो यह निर्णय बहुत सोच-विचार कर लिया गया था। यह सही है कि देश का बंटवारा धर्म के नाम पर हुआ था, पर हमारे तत्कालीन नेताओं ने कभी यह नहीं स्वीकारा कि हमारा भारत किसी एक धर्म को मानने वालों का देश बन जाये। दुनिया में शापद ही कोई और देश होगा जहां इतने धर्मों को मानने वाले लोग हों जितने हमारे देश में हैं। भारत ने हर धर्म का स्वागत किया है। हमारी

बहुधर्मिता हमारी ताकत है। यह सही है कि भारत में लगभग अस्सी प्रतिशत आबादी हिंदू है, लेकिन यहां हर धर्म को मानने वालों को अपनी आस्था के अनुसार जीने का अधिकार हमारा संविधान देता है। ऐसे में जब धर्म के आधार पर भेदभाव करने का कोई उदाहरण सामने आता है, और यदि उदाहरण मुख्यमंत्री स्तर का कोई व्यक्ति प्रस्तुत करता है तो हैरानी भी होती है, और पीड़ा भी।

कुछ ऐसा ही एक उदाहरण पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंद्र अधिकारी ने प्रस्तुत किया है। ‘सबका साथ, सबका विकास’ हमारे प्रधानमंत्री का प्रिय नारा है। वे और उनकी पार्टी के अन्य नेता इस बात का दावा भी करते हैं कि भाजपा की सरकारें बिना किसी भेद-भाव के हर धर्म को मानने वाले के विकास की चिंता करती

हैं। होना भी यही चाहिए। प्रधानमंत्री सिर्फ अपने दल का ही नेता नहीं होता, सारे देश का प्रधानमंत्री होता है वह। इसलिए, जब सबके साथ और सबके विकास की बात होती है तो उसका स्वागत ही होना चाहिए। पर पश्चिम बंगाल के भाजपा नेता शुभेंद्र खुलेआम यह कह रहे हैं कि इस नीति को बदला जाना चाहिए। हाल ही में उन्होंने यह कहा है कि ‘अब’ यह नीति नहीं चलेगी। उन्होंने घोषणा की है कि ‘जो हमारे साथ चलेगा, हम उसके साथ हैं’। स्पष्ट है, वे अपने राजनीतिक विरोधियों की ही नहीं, गैर हिंदुओं की भी बात कर रहे हैं।

ज्ञातव्य है कि कुछ असां बाद पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाले हैं। उसके कुछ बाद असम में चुनाव की बारी है। ऐसी स्थिति में इन दोनों राज्यों में धर्म के आधार पर भेदभाव की आशंकाएं मंडरा रही हैं। सवाल सिर्फ चुनाव में हार-जीत का नहीं है, सवाल उस बीमार सोच का है जिसके चलते देश की जनता को धर्म के आधार पर बांटा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भले ही किसी भी सोच के अंतर्गत ‘बंटेंगे तो कटेंगे’ की चेतावनी दी हो, पर यह चेतावनी सारे देश के लिए है हमने अपने संविधान में हर भारतीय को समता, न्याय और बंधुता के आधार पर समान अधिकार देने की व्यवस्था की थी। ऐसे में जब कोई शुभेंद्र अधिकारी चुनावी सभा में श्रोताओं को इस आशय की धमकी देता है कि ‘सड़क तब मिलेगी जब तुम धर्म बदलोगे’, तो हैरानी भी होती है और गुस्सा भी आता है।

ऐसा ही गुस्सा कोटद्वार के दीपक को आया

होगा जब उसने यह देखा कि 75 साल के एक मुसलमान व्यापारी को इसलिए परेशान किया जा रहा है कि उसकी दुकान के नाम में ‘बाबा’ जुड़ा हुआ है। तीस साल से चल रही है यह दुकान। तीस साल तक किसी को इस पर कोई आपत्ति नहीं हुई। तो, आज यह विवाद किसलिए एक सवाल सिर्फ ‘मोहम्मद दीपक’ नाम वाले युवक का नहीं है। देश के हर विवेकशील नागरिक के मन में यह सवाल उठना चाहिए। भारतीयता के आंगन में धर्म की दीवारें खड़ी करने वालों को यह बात क्यों समझ नहीं आ रही कि ऐसी हर दीवार आंगन को छोटा ही करती है। आज अपने आंगन को बांटना नहीं है, पूरे आंगन में धूप की ऊष्मा और रोशनी पहुंचाना हमारी आवश्यकता है। जिस साहस और समझदारी के साथ ‘मोहम्मद दीपक कुमार’ ने धर्म के नाम पर विद्वेष्ट फैलाने वालों का सामना किया है, आज देश के हर युवा में उस साहस और समझदारी की आवश्यकता है।

कोटद्वार में जो कुछ हुआ उसका एक हिस्सा यह भी है कि यह घटना इसी 26 जनवरी को, अर्थात् जब सारा देश गणतंत्र दिवस मना रहा था, तब घटी थी। यह वह दिन है जब हमने धर्म-निरपेक्ष भारत के लिए एक संविधान को अंगीकृत किया था। हर 26 जनवरी को हम उस संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेते हैं। हमारे नेता समता और न्याय के पक्ष में खड़े होंगे क्यों ज़रूरी नहीं समझते मोहम्मद दीपक ने यह बात समझी है। अब हर सोचने भारतीय को यह बात समझनी है।

लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।

खास खबर

ईसलनार हाईस्कूल की 19 छात्राओं को मिला सायकल



कोंडागांव। बस्तर विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष और कोंडागांव विधायक लता उसेंडी ने निःशुल्क सरस्वती सायकल वितरण योजना अंतर्गत आज ग्राम पंचायत ईसलनार के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की 19 छात्राओं को सायकल वितरण किया गया। साथ ही पांच लाख रुपए की लागत से पुलिया निर्माण कार्य का भूमिपूजन किया। कैरम, बॉलीबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट किट आदि अन्य आवश्यक खेल सामग्री का वितरण किया गया। समाज कल्याण विभाग द्वारा 03 हितग्राहियों को सहायक उपकरण प्रदान किया गया, इनमें जैतराम सोरो को श्रवण यंत्र, चौतीबाई को छड़ी और बाइसराम को ट्राइसिकल मिला।

फुटबॉल लीजेड बाईचुंग भूटिया ने बढ़ाया बच्चों का हैसाला

कोरबा। फुटबॉल के महान खिलाड़ी और पूर्व अंतरराष्ट्रीय स्ट्राइकर बाईचुंग भूटिया ने शहर के इंदिरा स्टेडियम में आयोजित विशेष बाल फुटबॉल कार्यक्रम में स्कूली बच्चों और युवा खिलाड़ियों ने अपने पसंदीदा खिलाड़ी का जोरदार स्वागत किया। बाईचुंग भूटिया ने खिलाड़ियों से संवाद करते हुए अनुशासन, मेहनत, टीमवर्क और खेल भावना का महत्व बताया। उन्होंने कहा कि सही मार्गदर्शन और निरंतर अभ्यास से खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना सकते हैं। बच्चों के साथ अभ्यास सत्र और छोटे मुकाबलों में भाग लेकर भूटिया ने नन्हे खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया।

गरियाबंद में लगेगा निःशुल्क बायोजिक हाथ वितरण शिविर

गरियाबंद। अस्थि बांधित दिव्यांगजनों को निःशुल्क कुत्रिम (बायोजिक) हाथ प्रदान करने के लिए राज्य स्तरीय शिविर का आयोजन जाएगा। इस योजना के अंतर्गत केवल वे दिव्यांग हितग्राही पात्र होंगे। जिनका हाथ कोहनी से नीचे, अर्थात कोहनी और कलाई के बीच कटा हुआ है। इच्छुक एवं पात्र दिव्यांगजन संबंधित जनपद पंचायत, नगरीय निकाय अथवा जिला कार्यालय समाज कल्याण विभाग, कक्ष क्रमांक 11 में आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए लीला राम ध्रुव से मोबाइल नंबर 62658-07116 पर संपर्क कर सकते हैं।

राज्य स्तरीय पैरा ओलंपिक एथेलेटिक्स में प्रथम रहे देवराम बालोद

बालोद। जिले के ग्राम पेपरपार के दिव्यांग खिलाड़ी देवराम पटेल ने राज्य स्तरीय पैरा ओलंपिक एथेलेटिक्स में आयोजित तीन खेलों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर प्रथम स्थान हासिल किया है। संयुक्त जिला कार्यालय में आज कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा ने दिव्यांग खिलाड़ी देवराम पटेल की उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उन्हें हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी तथा आगामी दिनों में होने वाले खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने शुभकामनाएं दी। पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ छत्तीसगढ़ द्वारा आयोजित 16वीं छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय पैरा ओलंपिक एथेलेटिक चैंपियनशिप 2025-26 में दिव्यांग खिलाड़ी देवराम पटेल ने तीन अलग-अलग स्पर्धाओं में प्रथम स्थान हासिल किया है। उन्होंने अपनी शारीरिक बाधाओं को पीछे छोड़ते हुए अपने असाधारण कौशल का प्रदर्शन करते हुए जैवलीन थ्रो (भाला फेंक), डिस्कस थ्रो (चक्रा फेंक) एवं शॉट पुट (गोला फेंक) में राज्य स्तर पर प्रथम स्थान कर बालोद जिले को गौरवान्वित किया है।

योजनाओं के प्रचार-प्रसार में मीडिया की भूमिका अहम

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय रायपुर प्रेस क्लब के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के शपथ-ग्रहण समारोह में शामिल हुए। उन्होंने प्रेस क्लब के नवनिर्वाचित अध्यक्ष मोहन तिवारी सहित समस्त कार्यकारिणी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि रायपुर प्रेस क्लब का इतिहास अत्यंत समृद्ध रहा है। यह देश के पुराने एवं प्रतिष्ठित प्रेस क्लबों में से एक है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नवनिर्वाचित पदाधिकारी प्रेस क्लब की गरिमा और प्रतिष्ठा को और ऊँचाइयों तक ले जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पत्रकार लोकतंत्र के सच्चे सेनानी हैं। पत्रकार समाज के प्रति सजग रहते हुए साहस के साथ गरीबों, वंचितों और आमजन की आवाज को बुलंद करते हैं। साथ ही शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों को जन-जन तक पहुंचाने में



गांधीडीह, लोरमी क्षेत्र की छात्राओं को मिला सुसज्जित छात्रावास, बेटियों की राह हुई आसान

श्रीकंचनपथ समाचार

मुंगेली। लोरमी के गांधीडीह क्षेत्र में कन्या शिक्षा को मजबूती प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण और दूरदर्शी पहल के अंतर्गत 04 कन्या छात्रावासों का एक ही परिसर में निर्माण पूर्ण करा लिया गया है। कलेक्टर कुन्दन कुमार के कुशल मार्गदर्शन में इन छात्रावासों का विधिवत शुभारंभ 01 जनवरी 2026 से किया जा चुका है, जिसके पश्चात छात्रावास में कक्षा पहली से लेकर कालेज तक की छात्राएं आवासरत हैं।

यह पहल न केवल छात्राओं की आवासीय समस्या का समाधान है, बल्कि उनके सर्वांगीण विकास की दिशा में एक ठोस पहल भी है। आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त शिवकुमार बांधे ने बताया कि पूर्व में छात्राओं को किराए के भवनों में रहना पड़ता था, जहां मूलभूत सुविधाओं की कमी व जगह का अभाव होने के कारण स्वीकृत सीट का अनुरूप छात्राओं को प्रवेश नहीं मिल पाता था।

अब स्वयं के भवन में संचालन होने से पर्याप्त स्थान, स्वच्छता, सुरक्षा, पेयजल, शौचालय, अध्ययन कक्ष एवं अन्य आवश्यक

व्यवस्थाएं संतोषजनक रूप से उपलब्ध हो पाएगी। इसका सीधा प्रभाव छात्राओं की शिक्षा, स्वास्थ्य और मानसिक विकास में एक सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

शासन की पहल पर नव-निर्मित कन्या छात्रावासों में छात्राओं की आवश्यकताओं को

ये है उद्देश्य

■ शाला त्यागी बेटियों की संख्या में कमी लाने की कोशिश, ताकि सबको मिले अवसर

■ अध्ययन के लिए बेहतर परिदृश्य निर्माण की कोशिश

■ छात्रावास में बेटियों की सुरक्षा का रखा जाएगा विशेष ध्यान

■ शारीरिक एवं मानसिक विकास में होगा सहयोगी

ध्यान में रखते हुए उच्च गुणवत्तापूर्ण निर्माण और सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। इन छात्रावासों में सुरक्षित एवं स्वच्छ आवास, पर्याप्त प्रकाश और वेंटिलेशन, शुद्ध पेयजल एवं स्वच्छ शौचालय, अध्ययन हेतु शांत एवं अनुकूल वातावरण के साथ ही सुरक्षा की दृष्टि से बेहतर प्रबंध जैसे सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, जिससे छात्राएं अब निश्चित होकर अपनी शिक्षा पर ध्यान केंद्रित कर सकें।

यह परियोजना केवल भवन निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह कन्या शिक्षा को प्रोत्साहित करने, विद्यालय छोड़ने की दर को कम करने तथा ग्रामीण क्षेत्र की बालिकाओं को आगे बढ़ने के समान अवसर प्रदान करने की दिशा में एक मजबूत कदम है। सुरक्षित छात्रावास की उपलब्धता से अभिभावकों का भरोसा भी बढ़ा है, जिससे अधिक संख्या में बालिकाएं शिक्षा से जुड़ सकेंगी।

पहचान भले ही अलग हो लेकिन सभी राज्यों की आत्मा एक भारत में हैं: राज्यपाल श्री डेका

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। राज्यपाल रमेन डेका के मुख्य आतिथ्य में आज राजभवन में 6 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों का स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर श्री डेका ने कहा कि सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की पहचान भले ही अलग-अलग हो लेकिन इन सब की आत्मा एक भारत में है।

केन्द्र सरकार के एक भारत-श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत विविधता में एकता की भावना को बढ़ावा देने के लिए सभी राज्य एक दूसरे का स्थापना दिवस मनाते हैं। इसी कड़ी में आज लोकभवन के छत्तीसगढ़ मण्डपम में आंध्रप्रदेश, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, झारखंड और नागालैण्ड राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों का स्थापना दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया।

इस अवसर पर श्री डेका ने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य विभिन्न राज्यों की भाषा, संस्कृति, परंपराओं और प्रथाओं के ज्ञान का आदान-प्रदान करना है जो आपसी समझ और सद्भाव को बढ़ावा देगा, जिससे भारत की एकता और अखंडता मजबूत होगी। इस परिप्रेक्ष्य में आज का कार्यक्रम एक गौरवपूर्ण क्षण है।



उन्होंने कहा कि हर राज्य का स्थापना दिवस, उस राज्य के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन होता है। राज्य की समृद्धि और विकास का गवाह यह दिन हमें अपने राज्य की स्थापना के मूल उद्देश्यों को सफलतापूर्वक पूरा करने और लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने का रास्ता दिखाता है। इन राज्यों का स्थापना दिवस, केवल उनके विकास की यात्रा का उत्सव नहीं है बल्कि भारत की विविधता और एकता का प्रतीक है।

रायपुर

पर्यटन और एडवेंचर स्पोर्ट्स से युवाओं को मिल रहे रोजगार के नवीन अवसर : मुख्यमंत्री श्री साय

- मुख्यमंत्री ने 10 रुपए की टिकट कटाकर मयाली नेचर कैंप में लिया एडवेंचर स्पोर्ट्स का आनंद

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज अलग अंदाज में नजर आए और उन्होंने 10 रुपए का टिकट कटाकर जिले के लोकप्रिय पर्यटन स्थल मयाली नेचर कैंप में साहसिक खेल गतिविधियों का आनंद लिया और कई नए एडवेंचर स्पोर्ट्स की औपचारिक शुरुआत भी की।

मुख्यमंत्री ने प्रवेश शुल्क अदा कर नेचर कैंप में प्रवेश करते हुए आम नागरिकों को नियमों के पालन और समानता का एक सशक्त संदेश दिया।

इस अवसर पर उनकी धर्मपत्नी कौशलया साय, विधायक गोमती साय, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अध्यक्ष डॉ. रामप्रताप सिंह, पर्यटन विभाग के सचिव डॉ. रोहित यादव, छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के प्रबंध संचालक विवेक आचार्य सहित जनप्रतिनिधिगण, अधिकारी-कर्मचारी एवं खेल प्रेमी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री श्री साय ने इस दौरान नेचर कैंप में विकसित अधोसंरचनाओं, सुरक्षा व्यवस्था, पर्यटकों के लिए उपलब्ध सुविधाओं तथा स्थानीय युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के पहल की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि प्रकृति-आधारित पर्यटन एवं साहसिक गतिविधियां न केवल पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देती हैं, बल्कि स्थानीय समुदाय के लिए रोजगार और आय के नए अवसर भी सृजित करती हैं।

मुख्यमंत्री ने 4 नए एडवेंचर स्पोर्ट्स का किया शुभारंभ



मुख्यमंत्री श्री साय ने मयाली नेचर कैंप में संचालित स्पोर्ट्स मोटर बाइक (एटीवी) की स्वयं चलाकर साहसिक पर्यटन का आनंद लिया। इसके साथ ही उन्होंने बंदूक से सटीक निशाना साधते हुए बैलून शूटिंग का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने आर्चरी शूटिंग में तीर चलाकर निशाना साधा और इस खेल की भी शुरुआत की। साथ ही उन्होंने मार्डटेन साइक्लिंग का शुभारंभ करते हुए स्वयं साइकिल चलाकर स्वस्थ जीवनशैली का संदेश दिया। नेचर कैंप में वॉल क्लाइंबिंग बोर्ड का उद्घाटन भी मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया।

इस दौरान वॉल क्लाइंबर तेज सिंह एवं तेजल भगत ने मुख्यमंत्री के समक्ष एवं वॉल क्लाइंबिंग कर अपने कौशल का प्रदर्शन किया, जिसकी मुख्यमंत्री ने सराहना



सौ दिवसीय बाल-विवाह मुक्त भारत अभियान का तृतीय चरण हुआ प्रारंभ

श्रीकंचनपथ समाचार

बीजापुर। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत 100 दिवसीय कार्यक्रम के तृतीय चरण में जिले में जनजागरूकता की व्यापक शुरुआत की गई है। कलेक्टर श्री सचिंत मिश्रा के निर्देशानुसार बाल विवाह के विरुद्ध जन अभियान के तहत ग्राम पंचायतों एवं नगरपालिका वार्डों के माध्यम से सामुदायिक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन 01 फरवरी 2026 से 08 मार्च 2026 तक किया जा रहा है।

2 फरवरी को ग्राम पंचायत गोल्हागुड़ा से अभियान की शुरुआत की गई। आयोजित कार्यक्रम में आमजनो को बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीति के दुष्परिणामों से अवगत कराया गया तथा बाल अधिकारों, किशोर-किशोरियों के स्वस्थ भविष्य एवं संबंधित कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी गई।

जागरूकता कार्यक्रम के दौरान बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की विस्तृत जानकारी, बाल विवाह के कानूनी परिणाम, बालिकाओं के शिक्षा अधिकार, स्वास्थ्य एवं पोषण से संबंधित लाभकारी योजनाओं तथा बाल



संरक्षण हेतु शासन द्वारा किए जा रहे प्रयासों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई। साथ ही ग्रामीण समुदाय, अभिभावकों, महिला समूहों एवं युवाओं से अपील की गई कि वे बाल विवाह न करें तथा कहीं भी बाल विवाह की सूचना तत्काल संबंधित विभाग को दें।

उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने बताया कि बाल विवाह न केवल कानूनी अपराध है, बल्कि यह बच्चों के शारीरिक, मानसिक एवं शैक्षणिक विकास में गंभीर बाधा उत्पन्न करता है। उन्होंने समाज के प्रत्येक वर्ग से बाल विवाह उन्मूलन में सक्रिय सहभागिता निभाने का आह्वान किया। उपस्थित ग्रामीणों, महिलाओं, किशोर-किशोरियों एवं विभिन्न सामाजिक संगठनों ने अभियान के प्रति सकारात्मक रुख प्रदर्शित करते हुए बाल विवाह मुक्त समाज के निर्माण हेतु पूर्ण सहयोग देने का संकल्प लिया।

मखाराल, लवन, सकरी और आरके में नए उप पंजीयक कार्यालय

रायपुर। प्रदेश में आम नागरिकों को रजिस्ट्री एवं पंजीयन से जुड़ी सेवाएं सहज, सुलभ और समयबद्ध रूप से उपलब्ध कराने की दिशा में राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। रजिस्ट्रीकरण अधिनियम-1908 के प्रावधानों के तहत भखारा (जिला धमतरी), लवन (तहसील मुख्यालय, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा), सकरी एवं राजकिशोर नगर (बिलासपुर) में चार नवीन उप पंजीयक कार्यालय खोलने के लिए प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है।

धमतरी जिला के भखारा में नवीन उप पंजीयक कार्यालय खोलने हेतु प्रशासकीय स्वीकृत दी गई है। इसी प्रकार जिला पंजीयक बलौदाबाजार-भाटापारा के अंतर्गत तहसील मुख्यालय लवन और बिलासपुर जिले के राजकिशोर नगर एवं सकरी में उप पंजीयक कार्यालय खोलने प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान किया गया है। इन नए उप पंजीयक कार्यालयों के खुलने से संबंधित क्षेत्रों के नागरिकों को रजिस्ट्री कार्य के लिए दूरस्थ जिला मुख्यालयों तक नहीं जाना पड़ेगा। इससे समय और धन की बचत होगी, भीड़ कम होगी।

गंजेपन से मुक्ति मात्र 1 घंटे में
COMPLETE FAMILY SALON
हेयर रिप्लेसमेंट, 100% संतुष्टि की गारंटी
पहले बाद में
JATU'Z
CUT N SHINE
93009-11331
रंगोली वैकल्प के सामने, जयसवाल इलेक्ट्रॉनिक के बाजू में इंडिया मार्केट, स्टेशन रोड, दुर्ग (छ.ग.)

GST NO. 22AHMPB9621P1Z2
PH.: 0788-4060131
अनुप ट्रेडर्स
आर्टिफिशियल ज्वेलरी के विक्रेता
लिंक रोड, केम्प-2, पावर हाउस, भिलाई
मो. 09826389666, 8839749539

खास खबर

युवाओं के लिए रोजगार का सुनहरा अवसर, 11 एवं 12 फरवरी को प्लेसमेंट कैम्प आयोजित

महासमुंद । जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र महासमुंद द्वारा राज्य के शिक्षित स्थानीय बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने 11 और 12 फरवरी 2026 को प्लेसमेंट कैम्प का आयोजन किया जा रहा है। जिला रोजगार अधिकारी ने बताया कि 11 फरवरी को रोजगार कार्यालय परिसर, मचेवा महासमुंद में एवं 12 फरवरी को जनपद पंचायत बागबाहरा में प्रातः 11.00 बजे से 2.00 बजे तक प्लेसमेंट कैम्प का आयोजन किया जाएगा। जिसमें निजी क्षेत्र के नियोजक एसपीएसजी सिक्क्योरिटी रायपुर के द्वारा सिक्क्योरिटी गार्ड के 150 पद के लिए 10वीं उत्तीर्ण आवेदकों की भर्ती प्रतिमाह 12000 से 19000 की वेतनमान पर एवं स्वतंत्र माइक्रोफिन पीवीटी रायपुर द्वारा फ़ैल्टड ऑप्तिस्मर एवं कलेक्शन ऑप्तिस्मर के 40 पदों के लिए 10वीं व 12वीं उत्तीर्ण आवेदकों की भर्ती प्रतिमाह 12200 की वेतनमान पर की जाएगी। जॉब फेयर पर उपस्थित होने वाले इच्छुक एवं योग्य आवेदक निर्धारित तिथि एवं स्थल पर शैक्षणिक योग्यता की छायाप्रति के साथ उपस्थित हो सकते हैं।

किसान सम्मान निधि एवं कृषि योजनाओं के लाभ हेतु एग्रीस्टेक किसान पंजीयन अनिवार्य

बालोद । भारत सरकार द्वारा किसानों के डिजिटल किसान आईडी कार्ड बनाने हेतु एग्रीस्टेक के अंतर्गत पंजीयन अनिवार्य किया है। कृषि विभाग के उप संचालक ने बताया कि भविष्य में समस्त कृषि योजनाओं एवं पी.एम.किसान का लाभ प्राप्त करने के लिए किसान आईडी आवश्यक है। उन्होंने बताया कि अब संयुक्त खाता धारक सभी कुषकों का अलग-अलग फ़र्मर (डिजिटल किसान) आईडी बनाना आवश्यक है। यदि भूमि रिकार्ड में एक से अधिक व्यक्तियों के नाम दर्ज है तो प्रत्येक खाताधारक को अपना स्वतंत्र किसान आईडी बनवाना होगा। डिजिटल किसान आईडी के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फ़सल बीमा योजना, विभिन्न कृषि अनुदान, सेवा सहकारी समितियों में समर्थन मूल्य पर धान विक्रय एवं कृषि ऋण जैसी महत्वपूर्ण सुविधाओं का लाभ प्राप्त होगा, किसान अपना डिजिटल किसान आईडी बनवाने के लिए बी-1, आधार कार्ड, आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नम्बर लेकर लोक सेवा केन्द्र अथवा सहकारी समितियों में संपर्क कर सकते है।

आयुष्मान आरोग्य मंदिर सिंघनगढ़ को प्रदेश में मिला दूसरा स्थान

कवर्धा । कबीरधाम जिले के विकासखंड सहसपुर लोहार अंतर्गत संचालित आयुष्मान आरोग्य मंदिर सिंघनगढ़ ने अपनी उत्कृष्ट सेवाओं और बेहतर स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए प्रदेश स्तर पर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। कायाकल्प आयुष 2024 के तहत स्वच्छता, सुव्यवस्था और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं के लिए राज्य में द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में आयुष्मान आरोग्य मंदिर सिंघनगढ़ पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया। कलेक्टर गोपाल वर्मा ने कायाकल्प आयुष 2024 के तहत 1172 संस्थाओं को पछड़कर दूसरा स्थान प्राप्त करने वाले आयुष्मान आरोग्य मंदिर सिंघनगढ़ की पूरी टीम को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। कलेक्टर वर्मा ने कहा कि यह उपलब्धि स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में टीम की प्रतिबद्धता, अनुशासन और समर्पण का परिणाम है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से आयुष्मान आरोग्य मंदिर सिंघनगढ़ ने स्वच्छता, सुव्यवस्थित व्यवस्था, मरीजों के प्रति संवेदनशील व्यवहार और गुणवत्तापूर्ण आयुष सेवाओं का उत्कृष्ट मॉडल प्रस्तुत किया है, वह पूरे जिले के लिए गर्व की बात है। उन्होंने आगे कहा कि कायाकल्प आयुष का उद्देश्य संस्थान की कार्यप्रणाली, रोगी संतुष्टि, औषधि उपलब्धता, उपचार की गुणवत्ता और समग्र स्वास्थ्य वातावरण को बेहतर बनाना है। कलेक्टर वर्मा ने चिकित्सा अधिकारियों, आयुष चिकित्सकों, फर्मासिस्ट, नर्सिंग स्टाफ एवं सख्योगी कर्मचारियों की सराहना करते हुए कहा कि यह सफलता पूरी टीमवर्क का परिणाम है।

ग्लोबल टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित होगा मयाली - साय

स्वदेश दर्शन योजना 2.0 के तहत जशपुर को मिली बड़ी सौगात, होम-स्टे, रिसोर्ट, पाथवे, लैंडस्केपिंग सहित आधुनिक पर्यटक सुविधाओं का होगा विकास

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर । मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज भारत सरकार की स्वदेश दर्शन योजना 2.0 की उप-योजना सीबीडीडी के अंतर्गत स्वीकृत मयाली-बगीचा विकास परियोजना का मयाली नेचर कैंप में विधिवत भूमिपूजन किया। लगभग 10 करोड़ रुपये की लागत से क्रियान्वित इस परियोजना के तहत मयाली, विश्व प्रसिद्ध मधेश्वर पर्वत (विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक शिवलिंग) तथा बगीचा स्थित कैलाश गुफा क्षेत्र में विभिन्न पर्यटन सुविधाओं का विकास किया जाएगा।

यह परियोजना क्षेत्र की प्राकृतिक, सांस्कृतिक एवं जनजातीय विरासत के संरक्षण के साथ-साथ समुदाय आधारित पर्यटन को सशक्त बनाएगी। इससे स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और जशपुर जिले को एक प्रमुख पर्यटन गंतव्य के रूप में नई पहचान मिलेगी।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री साय ने क्षेत्रवासियों को बधाई देते हुए कहा कि मयाली-बगीचा विकास परियोजना जशपुर जिले के पर्यटन विकास के लिए एक ऐतिहासिक पहल है। आज मयाली के विकास की मजबूत नींव रखी गई है। मयाली अब



पर्यटन मानचित्र पर तेजी से उभर रहा है और आने वाले समय में यह एक वैश्विक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मयाली की पहचान सदियों से मधेश्वर महादेव से जुड़ी रही है, जिसे विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक शिवलिंग माना जाता है। इस विकास परियोजना के माध्यम से मधेश्वर पर्वत के धार्मिक एवं पर्यटन महत्व को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी। परियोजना के अंतर्गत मयाली डेम के

समीप पर्यटक रिसोर्ट एवं स्किल डेवलपमेंट सेंटर का निर्माण किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि मयाली को एक समग्र इको-टूरिज्म और एडवेंचर डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। यहां के जंगल, झरने, पहाड़ और समृद्ध आदिवासी संस्कृति को देश-दुनिया के पर्यटकों तक पहुंचाया जाएगा। पर्यटन से होने वाली आय का सीधा लाभ स्थानीय लोगों को मिलेगा। श्री साय ने कहा इसी उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा होम-स्टे

विकास कार्यों से बदलेगी मयाली की तस्वीर, उमरेगा नया पर्यटन केंद्र

मयाली क्षेत्र को प्राकृतिक, धार्मिक एवं ग्रामीण पर्यटन के समग्र गंतव्य के रूप में विकसित किया जाएगा। परियोजना के अंतर्गत 5 पर्यटक कोटेंज, कॉन्फ्रेंस एवं कन्वेंशन हॉल, स्किल डेवलपमेंट सेंटर, भव्य प्रवेश द्वार, बाइंड्री वॉल, आधुनिक टॉयलेट सुविधा, लैंडस्केपिंग एवं पाथवे का निर्माण किया जाएगा। इन सुविधाओं से पर्यटकों के ठहराव एवं विभिन्न आयोजनों की बेहतर व्यवस्था होगी और रोजगार के अवसर सृजित होंगे। धार्मिक पर्यटन को सशक्त करने के लिए शिव मंदिर क्षेत्र में प्रवेश द्वार, टॉयलेट सुविधा, लैंडस्केपिंग एवं पाथवे का विकास किया जाएगा। वहीं बगीचा स्थित कैलाश गुफा परिसर में प्रवेश द्वार, पिकनिक स्पोर्ट, रेसिंग शेड, घाट विकास, पाथवे तथा सीढ़ियों एवं रेलिंग का जीर्णोद्धार किया जाएगा, जिससे पर्यटकों को सुरक्षित एवं सुविधाजनक अनुभव मिलेगा। यह समस्त कार्य भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा संचालित स्वदेश दर्शन योजना 2.0 के अंतर्गत स्वीकृत मयाली-बगीचा विकास परियोजना के माध्यम से किए जाएंगे। परियोजना के पूर्ण होने से पर्यटन गतिविधियों में वृद्धि, स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती तथा क्षेत्र की सांस्कृतिक-प्राकृतिक पहचान को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिलने की संभावना है।

नीति लागू की गई है, जिससे ग्रामीण परिवार पर्यटन गतिविधियों से सीधे जुड़कर आय अर्जित कर सकेंगे और पर्यटकों को स्थानीय संस्कृति को नजदीक से जानने का अवसर मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह परियोजना क्षेत्र के युवाओं के लिए नए अवसर लेकर आई है। स्किल डेवलपमेंट सेंटर में टूर गाइड, होटल सेवा, एडवेंचर स्पोर्ट्स, हस्तशिल्प एवं डिजिटल बुकिंग से संबंधित प्रशिक्षण दिया

जाएगा। इससे न केवल पर्यटन बल्कि जशपुर की सामाजिक और सांस्कृतिक विविधताओं को भी राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय पहचान मिलेगी।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री साय की धर्मपत्नी कौशलया साय, सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष एवं पथलगांव विधायक गोमती साय, छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के अध्यक्ष नीलू शर्मा, विभिन्न बोर्ड-निगमों के अध्यक्ष, जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी एवं बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

छत्तीसगढ़ ने रचा राष्ट्रीय कीर्तिमान: 10 माह में पूरा किया 5 लाख पीएम आवासों का निर्माण

पीएम आवास योजना



प्रभावी क्रियान्वयन का स्पष्ट प्रमाण

प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ द्वारा 5 लाख आवासों का निर्माण पूर्ण करना राज्य की प्रशासनिक क्षमता, मजबूत निगरानी व्यवस्था और जमीनी स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन का स्पष्ट प्रमाण है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सरकार ने गंभीर और जरूरतमंद परिवारों को पक्का घर देने के लक्ष्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। आवास निर्माण के साथ-साथ आजीविका, कौशल प्रशिक्षण और महिला सशक्तिकरण को जोड़कर योजना को समग्र विकास का माध्यम बनाया गया है। यह राष्ट्रीय कीर्तिमान छत्तीसगढ़ की सुशासन पर आधारित विकास नीति की सफलता को दर्शाता है।

विजय शर्मा, उपमुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन

27 हजार 224, बलरामपुर में 27 हजार 12, कोरबा में 26 हजार 839 तथा रायगढ़ जिले में 26 हजार 707 आवासों का निर्माण पूर्ण कर इन जिलों ने राज्य की समग्र उपलब्धि में अग्रणी भूमिका निभाई है इसके अतिरिक्त मस्तूरी, आरंग, डभरा, बिल्हा, पाली एवं जैजैपुर जनपद पंचायतों द्वारा भी 7,500 से अधिक प्रधानमंत्री आवासों का निर्माण कर उल्लेखनीय योगदान दिया गया है।

उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ में आवास निर्माण के साथ-साथ आजीविका सृजन को भी

समान प्राथमिकता दी गई है। महिला स्व-सहायता समूहों से जुड़ी हजारों महिलाओं ने सीएलएफ बैंक का कार्य प्रारंभ किया है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति मिली है। इस पहल के परिणामस्वरूप 8,000 से अधिक महिलाएँ 'लखपति दीदी' के रूप में आत्मनिर्भर बनकर उभरी हैं, जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को कौशल से जोड़ने के

शहीद वीर नारायण सिंह संग्रहालय के फेस-2 का कार्य शीघ्र होगा प्रारंभ: सोनमणि बोरा

श्रीकंचनपथ न्यूज



रायपुर । नवा रायपुर में शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक सह जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय का राज्योत्सव के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों से लोकार्पण एवं छत्तीसगढ़ आदिवासी संग्रहालय का मई 2025 में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय द्वारा लोकार्पण पश्चात, इनकी तेजी से बढ़ती लोकप्रियता के बाद अब शहीद वीर नारायण सिंह आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय फेस-2 का कार्य शीघ्र ही प्रारंभ किया जाएगा।

प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने इस संबंध में आज आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, नवा रायपुर स्थित सभाकक्ष में आर्किटेक्ट, इंजीनियर्स, आर्टिस्ट एवं विभागीय अधिकारियों के साथ आवश्यक बैठक कर

कार्ययोजना के संबंध में जानकारी ली एवं आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। प्रमुख सचिव बोरा ने बताया कि फेस-2 के अंतर्गत एक कैफेटेरिया, गढ़ कलेवा एवं अन्य दुकानें खोली जानी हैं इस संबंध में अंतिम रूपरेखा पर चर्चा की जा रही है। इसके बाद निर्धारित प्रक्रिया अनुसार आगे की कार्यवाही की जाएगी। फेस-2 के अंतर्गत ही आकर्षक बागवानी, परिसर के भीतर स्थित नंद सागर का सौंदर्यीकरण, फ़ोंउटेन एवं पार्किंग को बेहतर व्यवस्था की जाएगी। बैठक में आदिम जाति

उल्लेखनीय है कि शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक सह

हजार बच्चों को हॉस्टल में रहने के लिए सुविधाएं विकसित की गई हैं।

प्रमुख सचिव बोरा ने बताया कि राजधानी रायपुर में बनाए जा रहे इन हॉस्टलों में रहने वाले विद्यार्थियों को सिविल सर्विसेस, एनडीए, क्लेट, नेट, स्लेट, पीटी, पीएमटी, आईआईटी, मेडिकल सहित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाएगी। सड़ू का पूरा परिसर लगभग 18 एकड़ तथा डूंडा का हॉस्टल परिसर 10 एकड़ से अधिक भूमि में विकसित किया गया है।

गौरतलब है कि नवनिर्मित हॉस्टलों में एकलव्य ड्रामर छात्रों के लिए कोचिंग हेतु 500 सीटर, ओबीसी बालक-बालिकाओं हेतु

सौ-सौ सीटर, अनुसूचित जनजाति के बालिकाओं के व्यवसायिक शिक्षा, शोध एवं अन्य उच्च शिक्षा हेतु 250 सीट शामिल है। इसकी लागत 35 करोड़ 30 लाख 64 हजार रूपए है। इस मौके पर संयुक्त सचिव बी.एस. राजपुत, अपर संचालक आरएस भोई, ईई त्रिदीप चक्रवर्ती, सहायक आयुक्त शरदचन्द्र शुकला सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने आज ज्ञानोदय हब सहित विभाग द्वारा संचालित किए जा रहे हॉस्टलों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को कालीबाड़ी और पेंशनबाड़ा स्थित पुराने छात्रावासों के स्थान पर आधुनिक सुविधाओं से लैस नया चार-चार मंजिला हॉस्टल भवन तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने सड़ू और डूंडा में तैयार पांच हॉस्टल भवन का भी निरीक्षण किया। यहां लगभग एक

जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि भारत सरकार द्वारा गणतंत्र दिवस, 26 जनवरी, 2026 के अवसर पर आयोजित परेड में इस संग्रहालय को प्रदर्शित किया गया। इससे छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश में जनजातीय वीर नायकों की अमर गाथाओं, उनकी देश भक्ति, अग्रिम साहस और बलिदान की परंपरा को नई पीढ़ी को जानने समझने का अवसर राष्ट्रीय मंच पर प्राप्त हुआ। इस संग्रहालय के उद्घाटन के बाद तीन माह में लगभग एक लाख से अधिक पर्यटकों द्वारा भ्रमण कर लिया गया है।

बैठक में कांकर एवं कोडांगांव में राजस्व/वन भूमि में निर्मित एकलव्य आदर्श आवासीय विकास के हस्तांतरण प्रक्रिया पर भी चर्चा की गई।

CAR DECOR

House Of Exclusive
Seat Cover,
Car Stereos Matting &
Sun Control Film &
Other Accessories

Shop No.3 Nafish Tower.
Opp. Indian Coffee House,
Akashganga, Bhilai

Mo.9300771925, 0788-4030919

K. Satyanarayan

SAIRAM

Mobile Accessories

मोबाईल शॉप में
कार्य करने हेतु
लड़कों की
आवश्यकता है

7000415602

Shop No. 78, Himalaya Complex, Supela, Bhilai

ROCKEY INDUSTRIES

FURNITURE PALACE

Deals in: (Steel & Wooden)
Luxury & Imported Furniture

Akash Ganga, Supela, Bhilai Ph. 2296430

चौरसिया ज्वेलर्स

आकर्षक सोने चांदी के अग्रगण्य के निर्माता एवं विक्रेता

बेन्ट्स एवं ग्रहदाल उपलब्ध यहां
उचित व्याज दर पर ग्रहली रखी जाती है

मुक्तिधाम रोड, रामनगर, सुपेला, भिलाई

9827938211, 9827171332

Jaquora Roca

Sanitarywares, Tiles,
CPVC Pipes &
Bathroom Fittings etc.

Supela Market, Bhilai

PH. 0788-4030909, 2295573

खास खबर

बिल्डिंग ठेकेदार के घर 3 लाख की चोरी

दुर्ग। ज़िले में चार से ज्यादा चोरों ने बिल्डिंग ठेकेदार के घर में लाखों रुपए की चोरी को अंजाम दिया है। चोरों ने सोने-चांदी के जेवर और बड़ी रकम के कैश चोरी कर लिए। यह मामला अमलेश्वर थाना इलाके की है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। सीसीटीवी और अन्य सबूतों से आरोपियों की तलाश की जा रही है। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ भी कर रही है और जल्द ही आरोपियों को पकड़ने का दावा किया गया है। पीड़ित ने चोरी हुए जेवरत से जुड़े करीब 18 बिल भी पुलिस को दिए हैं। ग्राम मोतीपुर खवहरिया रोड में रहने वाले राम स्वरूप साहू ने थाना अमलेश्वर में शिकायत दी है कि उनके घर से लाखों रुपए के जेवर और नकदी चोरी हो गए। उन्होंने बताया कि चोर घर के पीछे के दरवाजे से अंदर आए। मुख्य दरवाजे का लॉक टूटा नहीं था, लेकिन कमरे का लॉक टूटा हुआ मिला। घर के भीतर सामान बिखरा हुआ था और अलमारी का ताला तोड़कर कीमती सोने-चांदी के जेवरत चुरा लिए गए। पुलिस ने चोरी हुए सामान की कीमत करीब 3,18,070 रुपए आंकी है। चोरी में 34 सोने के जेवर, 14 चांदी के जेवर शामिल हैं। इसके अलावा लाखों रुपए कैश की भी चोरी होने की जानकारी दी गई है।

खेत में पहुंचा तेंदुए का शावक इलाके में गंवा हड़कंप

नगरी। नगरी ब्लॉक के सिहावा-नगरी वर्नांचल क्षेत्र में खेतों के बीच हटुएं का एक शावक मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही ग्रामीणों की भीड़ जुट गई, वहीं वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर शावक को सुरक्षित रेस्क्यू कर जंगल सफारी, नया रायपुर भेज दिया। यह मामला बिरगुड़ी वन परिक्षेत्र के छिपली पारा गांव का है, जहां करीब 5 से 6 माह का तेंदुएं का शावक श्रृंगी ऋषि पहाड़ी के नीचे स्थित जंगल से भटककर राजस्व क्षेत्र में पहुंच गया था। खेतों में शावक दिखते ही ग्रामीणों में दहशत फैल गई और तत्काल वन विभाग को सूचना दी गई। जांच में उसकी हालत सामान्य पाई गई, हालांकि वह पानी में भीगा हुआ था, जिससे उसके नाले या जलस्रोत से भटकने की आशंका जताई जा रही है। वन परिक्षेत्र अधिकारी सुरेंद्र कुमार अजय ने बताया कि शावक पूरी तरह स्वस्थ है।

सब्जी मंडी में मवेशी लोगों पर कर रहे हमला

दुर्ग। दुर्ग सब्जी मंडी इंदिरा मार्केट दुर्ग में शाम होते ही पशुओं का जमावड़ा बढ़ जाता है, जिससे आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सब्जियां खरीदने के दौरान कई बार लोग मवेशियों के हमले से घायल भी हो चुके हैं। नगर निगम के अफसरों को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए ताकि आम लोगों की परेशानी दूर हो।

ट्रेन से गिरकर आडिशा के युवक की मौत

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। जिले के अभनपुर थाना क्षेत्र में ट्रेन से गिरने के कारण आडिशा के एक युवक की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही अभनपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई शुरू की। मृतक रेलवे की परीक्षा देने ओडिशा से रायपुर आया था। मिली जानकारी के अनुसार गोलाबंध नुआपाड़ा ओडिशा निवासी जय राम मांझी, पिता कोखसरिया मांझी, उम्र 21 वर्ष 4 फरवरी 2026 को रायपुर रेलवे स्टेशन से शाम करीब 4 बजे रायपुर से अभनपुर जाने के लिए ट्रेन का टिकट लेकर रवाना हुआ। मृतक की जेब से मिले टिकट से इस बात की पुष्टि हुई है। बताया गया कि जय राम मांझी रेलवे से संबंधित परीक्षा देने के लिए ओडिशा के बालांगीर से रायपुर आया था। उसका परीक्षा केंद्र कलिंग यूनिवर्सिटी में निर्धारित था। मृतक के चाचा छबि लाल मांझी, जो इस घटना के बाद मौके



पर पहुंचे, पुलिस को बताया कि परीक्षा देने के बाद जय राम रायपुर से अभनपुर की ओर जा रहा था। ट्रेन के सीबीडी रेलवे स्टेशन पहुंचने पर वह समय पर नीचे नहीं उतर सका। ट्रेन के आगे बढ़ जाने पर उसने जल्दबाजी में उतरने का प्रयास किया, इसी दौरान उसका संतुलन बिगड़ गया और वह ट्रेन से नीचे गिर गया। पुलिस का कहना है कि प्रथम दृष्टया मामला दुर्घटना का प्रतीत हो रहा है, जिसमें चलती ट्रेन से उतरने के प्रयास के दौरान गिरने से युवक की मौत हुई है।

खेत में जुआ खेल रहे सात गिरफ्तार

राजनांदगांव। छुईखदान पुलिस ने खेत में जुआ खेल रहे 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से 9100 रुपए नकद व ताशपत्ती जब्त की गई है। छुईखदान पुलिस ने बताया कि बुधवार दोपहर शहर से लगे खेत में जुए के फंड जमे होने की सूचना मिली।

इसके बाद टीम ने मौके पर दबिश दी। जहां से भारत कुंभकार, लोकेश दास, मुकेश वैष्णव,



अशोक सारवा, रमेश देवांगन, चेतन देवांगन और दिनेश कुंभकार को हिरासत में लिया गया। जुआ एकट में कार्रवाई की गई है।

श्रीकंचनपथ न्यूज

भिलाई। युवाओं को नशे के जाल से बचाने दुर्ग पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में पुलिस ने रेड कर गोंगो पेपर, हुक्का सामग्री और भारी मात्रा में नशीला तंबाकू बरामद किया है। एसएसपी विजय अग्रवाल के निर्देश पर 35 से अधिक टीमों द्वारा एक साथ रेड कार्रवाई की गई। इस मामले में 16 दुकानदारों पर, कोटपा एक्ट के तहत कार्रवाई की है। इस दौरान पुलिस ने करीब 2 लाख रुपए की नशीली सामग्री जब्त की है।

दुर्ग पुलिस द्वारा युवाओं में बढ़ते नशे के प्रचलन, विशेषकर गांजा सेवन को रोकने के उद्देश्य से एक विशेष अभियान संचालित किया गया। अभियान के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक के



आदेशानुसार 35 से अधिक पुलिस टीमों का गठन कर एक साथ शहर के विभिन्न क्षेत्रों में समन्वित रेड कार्रवाई की गई। रेड कार्रवाई के दौरान यह बात सामने आई कि शहर के विभिन्न पान ठेले,

गुमटियां एवं डेली नीड्स दुकानों पर गांजा पीने के लिए 'गोंगो/रोलिंग पेपर', चिलम, हुक्का फ्लेवर एवं प्रतिबंधित जर्दायुक पान मसाला का अवैध रूप से विक्रय किया जा रहा है।

इसके बाद संयुक्त टीमों द्वारा नियमानुसार तलाशी लेकर करीब 2 लाख रुपए मूल्य के भारी मात्रा में गोंगो रोलिंग पेपर, हुक्का फ्लेवर, चिलम एवं प्रतिबंधित जर्दायुक पान मसाला जब्त किया गया। शैक्षणिक संस्थानों के आसपास एवं सार्वजनिक स्थलों पर कोटपा एक्ट के उल्लंघन पर संबंधित दुकानों के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत इस्तागासा प्रस्तुत कर पृथक से प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई है। जब्त सामग्री की सप्लाय चैन का भी पता लगाया गया है, जिनके विरुद्ध आगामी वैधानिक कार्रवाई प्रस्तावित है।

कार्रवाई के दौरान मोहन नगर से 8, स्मृतिनगर से 5, नेवई से 2 एवं दुर्ग क्षेत्र से 1 दुकान पर रेड की गई। इस दौरान कुल 17 लोगों के खिलाफ काटपा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है।

खाना खिलाने के बहाने मासूम बच्ची से किया रेप

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। रायपुर में 8 साल की बच्ची को किडनेप कर उससे रेप किया गया है। लड़की सिमल पर पैसे मांगकर गुजर बसर करती थी। इसी दौरान खाना खिलाने के बहाने कार सवार ड्राइवर ने उसे गाड़ी में बैठाया, फिर वीआईपी रोड पर ले जाकर वारदात को अंजाम दिया।

पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की मदद से बुधवार-गुरुवार की रात 3 बजे आरोपी ड्राइवर नवीन को गिरफ्तार कर लिया है। मामला तेलीबांधा थाना इलाके का है।

बता दें कि 2 सप्ताह पहले भी 9 साल की बच्ची से रेप हुआ था। सिविल लाइन थाना क्षेत्र में आरोपी अब्दुल अंसारी (65) ने अपने ही मोहल्ले की एक बच्ची का 5 दिनों तक रेप किया था। वह बच्ची को चॉकलेट देकर अपने साथ ले जाता और उससे रेप करता था।

दरअसल, तेलीबांधा स्थित सिमल पर नाबालिंग लड़की वाहन चालकों से पैसे मांगकर गुजर बसर करती है। बुधवार की रात 9.30 बजे 2 नाबालिंग अपने साथियों के साथ सिमल पर



लोगों से पैसे मांग रही थी।

इस दौरान स्विफ्ट कार में सवार आरोपी नवीन (21) ने खाना खिलाने का झांसा देकर पीड़िता और उसकी सहली को गाड़ी में बिठाया, फिर ललित महल की ओर ले गया। सहली को कुछ खाने का सामान लाने के लिए ललित महल के पास भेज दिया और कार को आगे ले जाकर लड़की से दुष्कर्म किया। बहुत देर तक उन्होंने पुलिस को सूचना दी।

मानिकपुर कोयला खदान में हादसा, 170 फीट गहरी खाई में गिरने से मजदूर की मौत

खदान क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उठे सवाल



निवासी भगत कुमार मरावी (42 वर्ष) बुधवार दोपहर खदान क्षेत्र में गिरा था। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक वह कोयला चोरी करने के लिए खदान की गहराई में उतरने का

प्रयास कर रहा था, इसी दौरान उसका पैर फिसल गया और वह गहरे गड्ढे में जा गिरा। ऊंचाई से गिरने के कारण उसे गंभीर चोटें आईं और उसकी मौके पर ही मौत हो

गई। घटना की सूचना मिलते ही मानिकपुर चैकी पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। सीएसपी प्रतीक चतुर्वेदी ने बताया कि खदान में गिरने से एक मजदूर की मौत की घटना सामने आई है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इस घटना ने एक बार फिर खदान क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं।



रायगढ़ कार्बन प्लांट विस्फोट केस : एकआईआर दर्ज

रायगढ़। रायगढ़ के मंगल कार्बन प्लांट में फर्नेस विस्फोट से बड़ा हादसा हो गया, जिसमें आठ कर्मचारी गंभीर रूप से झुलस गए। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। वहीं इस मामले में अब प्रबंधन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में स्थित मंगल कार्बन प्लांट में बीते दिन एक बड़ा हादसा सामने आया था। प्लांट की फर्नेस (भट्ठी) में हुए भीषण विस्फोट के कारण आठ लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं। जानकारी के अनुसार, यह हादसा सुरक्षा मानकों की घोर अनदेखी और लापरवाही का परिणाम बताया जा रहा है। घटना के बाद, प्रबंधन के खिलाफ दो लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है।

सीसीएफ आलोक तिवारी व डीएफओ उत्तम गुप्ता के निर्देश पर एसडीओ देवलाल दुर्गा व माचकोट रेंजर सुमित साहा के नेतृत्व में की गई कार्रवाई में परिक्षेत्र सहायक बर्नसिंह कर्मा, बाबुराम कश्यप, बुधसन बघेल, लच्छूराम मरकाम व अन्य कर्मी शामिल थे।

जगदलपुर में चीतल के शिकार व अतिक्रमण के आरोपी गिरफ्तार



श्रीकंचनपथ न्यूज

जगदलपुर। बस्तर वनमंडल के तहत माचकोट रेंज में चीतल के शिकार और सुकमा से आकर माचकोट में अवैध अतिक्रमण करने के मामले में वन विभाग के अमले ने 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि शहर से लगे ग्राम बिलौरी में चीतल के शिकार और सुकमा जिले से आए 14 आरोपियों द्वारा माचकोट क्षेत्र में वनभूमि पर अतिक्रमण का प्रयास करने के मामले में वन विभाग ने वन अपराध दर्ज कर कार्रवाई की है। आरोपियों को न्यायालय में पेश



भिलाई मसाला उद्योग



आरोपियों का विवरण

अभिनंदन सिंह, उम्र 30 वर्ष, प्रगति नगर चित्रांश साहू उर्फ सोनू, उम्र 23 वर्ष, रुआबांधा बस्ती, विजेश बारवे, उम्र 44 वर्ष, मुखर्जी नगर, सिकोला भाठा, मोहन नगर देवेन्द्र भोसले, उम्र 20 वर्ष, सिकोला भाठा, दुर्ग (सुनील पान) शंकर लाल बंछोर, उम्र 65 वर्ष, संतराबाड़ी, मोहन नगर (बंछोर चाय पान जनरल) संजय कुमार बड़ानी, उम्र 48 वर्ष, संताराबाड़ी, दुर्ग (संजय पान मसाला) लोकेश कुमार साहू, उम्र 35 वर्ष, उरला, मोहन नगर (श्री गणेश किराना) कुशाल प्रजापति, उम्र 30 वर्ष, तितुरडीह, नयापारा, मोहन नगर (बनारसी पान भंडार) अर्जुन यादव, उम्र 46 वर्ष, सिकोला

भाठा, मोहन नगर (यादव होटल) राजकुमार महोबिया, उम्र 39 वर्ष, लुचकी पारा, दुर्ग (अजय पान पैलेस) राजेश कुमार द्विवेदी, उम्र 57 वर्ष, पांच रास्ता, सुपेला (फायर पान पैलेस एवं डेली नीड्स, स्मृतिनगर) मनोज कुमार चौहान, मॉडल टाउन, स्मृतिनगर (पार्वती किराना स्टोर्स) त्रिवेणी साहू, उम्र 50 वर्ष, जुनवानी, लकी चंदानी, उम्र 43 वर्ष, कादम्बरी नगर, मोहन नगर (शीतल डेली नीड्स, स्मृतिनगर) भगवान साहू, हाउसिंग बोर्ड (गणेश पान दुकान, मॉल चौक, स्मृतिनगर/मिलाई) विमल जसवानी, उम्र 23 वर्ष, सिंधी कॉलोनी, दुर्ग (कला प्रोविजन स्टोर्स, इंदिरा मार्केट) ।



विष्णु के सुशासन में महिला सशक्तीकरण



महिला शक्ति को सम्मान

69 लाख से अधिक महिलाओं को महतारी वंदन योजना के अंतर्गत प्रतिमाह **₹1000** की सहायता

प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना के अंतर्गत 4.81 लाख महिलाओं को **₹237 करोड़** की सहायता

19 लाख से अधिक महिलाओं को पूरक पोषण आहार की सुनिश्चितता

महिला सुरक्षा के लिए **सखी वन स्टॉप सेंटर** और महिला हेल्पलाइन **181** की स्थापना

महिलाओं को रोजगार मूलक कार्यों के जरिए स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने के लिए पंचायत स्तर पर **179 महतारी सदनों** का निर्माण



श्री विष्णु देव साय
माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री



हमसे जुड़ने के लिए
QR स्कैन करें

[/ChhattisgarhCMO](#)

[/DPRChhattisgarh](#)

www.dprcg.gov.in



सुशासन से समृद्धि की ओर